प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जब भी कोई महिला अपने लिए खड़ी होती है, तो संभवत: अनजाने में वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। - माया एंजेलो

शीर्ष अदालत का यह कहना कि केंद्र और केरल सरकार के प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी साथ मिलकर बैठें और बातचीत कर मुद्दे का समाधान खोजें, स्वागतयोग्य है। लेकिन वित्तीय प्रबंधन के मसलों में जरूरी है कि राज्य अपनी व्यवस्था सुधारें, तभी स्थायी किस्म के समाधान की उम्मीद की जा सकती है।

राज्य भी तो जिम्मेदार बनें

शीर्ष अदालत का यह कहते हुए कि राज्यों में वित्तीय कुप्रबंधन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, केंद्र और केरल सरकार को अपने मतभेदों को दूर करने का परामर्श देना, वर्तमान स्थितियों में सबसे तार्किक और समयानुकूल समाधान दिखता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा उधार की सीमा निर्धारित किए जाने के खिलाफ पिछले वर्ष दिसंबर में केरल की एलडीएफ सरकार ने सर्वोच्च अदालत का यह कहते हुए दरवाजा खटाखटाया था कि केंद्र मनमाना बर्ताव करते हुए उसके अधिकारों को छीन रहा है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि वह राज्यों के खर्च व उधार को नियंत्रित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 (3) और 294 (4) पर निर्भर है, अलबत्ता उधार की सीमा की सिफारिश तो पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर वित्त आयोग द्वारा की जाती है। इस तथ्य को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि 2020-21 से 2023-24 के बीच केरल की पिनाराई विजयन सरकार को केंद्र की तरफ से 15वें वित्त आयोग के सुझावों से कहीं ज्यादा आर्थिक संसाधन मुहैया कराए गए थे। जैसा कि केरल सरकार खुद अदालत में स्वीकार चुकी है, 2016 से 2023 के बीच केरल को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है, जो राज्य में आर्थिक संसाधनों के कुप्रबंधन को ही दिखाता है। जाहिर है कि आज अगर दक्षिण का यह राज्य, जो देश में सर्वाधिक साक्षर होने के साथ मानव विकास सूचकांक में भी अव्वल है, दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, तो इसके लिए राज्य सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, अदालत का यह सवाल भी जायज है कि वित्तीय आपातकाल की दुहाई देती केरल सरकार अतिरिक्त धनराशि की मांग करने से पहले केंद्र द्वारा दी जा रही 13,608 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकार क्यों नहीं करती? चूंकि, राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण सार्वजनिक वित्त प्रबंधन का देश की क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ता है, अदालत का यह

कहना कि केंद्र और केरल सरकार के प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी साथ मिलकर बैठें और बातचीत कर समस्या का समाधान खोजें, स्वागतयोग्य है। यह दूसरे राज्यों के लिए भी एक सबक है कि एक राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे देखना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के मसलों में जरूरी है कि राज्य अपनी व्यवस्था सुधारें, तभी स्थायी किस्म के समाधान की उम्मीद की जा सकती है।

महिलाएं देश बनाती हैं

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से न सिर्फ आर्थिक विकास, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी जमीन तैयार होती है। उनके लिए वित्तीय अवसर पैदा करने से वह तो मजबूत होती ही हैं, परिवार के साथ-साथ देश भी मजबूत होता है।

लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन
पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण की पुत्री

हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति ने महत्वपूर्ण गति पकड़ी है। वर्तमान में देश अपने 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सपने की बुनियाद मजबूत कर रहा है, जल्द ही यह तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने वाला है और अंततः 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व को स्वीकार करें।

खेल, व्यवसाय से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक, यानी जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने साबित किया है कि भारत की प्रगति में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उनका वित्तीय सशक्तीकरण आवश्यक है, ताकि वे देश के विकास को प्रगतिशील और समावेशी बनाने में बदलाव की वाहक बन सकें।

आज हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि महिला सशक्तीकरण महज एक नारा नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने से विभिन्न आर्थिक-सामाजिक पहलुओं पर ठोस परिणाम सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने से न केवल जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है और समग्र कल्याण में सुधार होता है। एक रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश लैंगिक रूप से समान अर्थव्यवस्था वाले देशों में लैंगिक रूप से असमान अर्थव्यवस्था वाले देशों की तुलना में औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत अधिक है। विकास दर में यह अंतर 15 साल की अवधि में जीडीपी के अतिरिक्त 20 फीसदी के बराबर है। यहां तक कि मैकिंजे की एक रिपोर्ट भी इस बात पर प्रकाश डालती है कि महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने से 2025 तक भारत की जीडीपी 770 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकती है। इसलिए मजबूत आर्थिक विकास करने वाले भारत द्वारा श्रमबल में

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनका समर्थन करने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। इसे हासिल करने के लिए संगठनों को श्रमबल में विविधता लाने के महत्व और आवश्यकता को महसूस करने की जरूरत है। इसे सुनिश्चित करने से अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है और विविध विचारों और दृष्टिकोण वाली कंपनियों को लाभ भी हो सकता है।

चूंकि महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं और व्यक्तिगत एवं पेशेवर स्तर पर विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां संभालती हैं, इसलिए संगठनों को उन्हें काम एवं जीवन में बेहतर संतुलन बनाने में मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वित्तीय विकास के लिए उन्हें अपने निजी जीवन का त्याग न करना पड़े। लचीली कार्य-व्यवस्था प्रदान करने, प्रगतिशील अवकाश नीति अपनाने, बाल-देखभाल सहायता सुनिश्चित करने एवं उन्हें अन्य सुविधाएं देने से इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये प्रयास महिलाओं की भलाई और उन्हें बेहतर रोजगार संतुष्टि प्रदान कर कार्य में सार्थक योगदान देने में सक्षम बना सकते हैं। नेतृत्व में विविधता लाने के लिए संगठन के भीतर वरिष्ठ भूमिकाओं में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अवसर भी पैदा करने होंगे। सीखने की पहल, कोचिंग एवं सलाह के माध्यम से महिला प्रतिभाओं की पहचान करने औरउन्हें नेतृत्वकारी भूमिका की खातिर तैयार करने से वे अपने कॅरिअर को कुशलता एवं आत्मविश्वास के साथ बढ़ाने में सक्षम हो सकती हैं और बेहतर समस्या समाधान, तेजी से निर्णय लेने और विकास एवं सफलता के लिए समग्र सुधार में संगठनों का समर्थन कर सकती हैं।

इस समय देश के आर्थिक विकास ने एक लहर पैदा कर दी है, जिससे महिलाओं के वित्तीय विकास की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में, उन्हें मौजूदा और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करने एवं समर्थन देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, भारत फिलहाल एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। इससे महिलाओं के डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है, ताकि वे अपनी आय, रोजगार की संभावनाएं बढ़ा सकें और ज्ञान हासिल करके समग्र विकास कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट कवरेज का विस्तार करना, किफायती इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना, महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल का समर्थन करना और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना जरूरी है, जो बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ा सकता है और उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से सिर्फ आर्थिक विकास ही हासिल नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक सशक्त साधन के रूप में भी काम करता है। उनके लिए वित्तीय अवसर पैदा करने और उन्हें आय के नियमित स्रोत से जोड़ने से न केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि बढ़ती है, बल्कि वे अपने परिवार का सहयोग करने में भी सक्षम होती हैं। वित्तीय सशक्तीकरण से उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। यह उन्हें अपने बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करने तथा भविष्य के लिए स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त पीढ़ियों के निर्माण में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सशक्त महिलाएं बदलाव का वाहक बनती हैं और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। वे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं एवं मानदंडों को चुनौती देने, पुरुषों की बराबरी करने, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और एक समावेशी समाज बनाने के लिए परिवार और समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं।

कुल मिलाकर, महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना जरूरी है, ताकि वे भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी ताकत के रूप में उभर सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए महिला सशक्तीकरण की चर्चा करना न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि जरूरी भी है। उन्हें जरूरी समर्थन, प्रोत्साहन और मान्यता देने से यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि वे आगे बढ़ें और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती रहें।

जीवन धारा

जग्गी वासुदेव

आदियोगी ने बताया कि आपका जो वर्तमान ढांचा है, यही सीमा नहीं है। आप इस ढांचे को पार कर जीवन के अलग पहलू की ओर बढ़ सकते हैं। योग से मानव तंत्र को परम संभावना में रूपांतरित किया जा सकता है।

शिव आदियोगी हैं और आदि गुरु भी

जब हम 'शिव' कहते हैं, तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। 'शिव' का शाब्दिक अर्थ है- 'जो नहीं है'। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रम्हांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसके अलावा, सब एक खालीपन है, जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वह गर्भ हैं, जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, उसी में सब कुछ फिर से समा जाता है।

शिव को 'अस्तित्वहीन' बताया जाता है, एक अस्तित्व की तरह नहीं। उन्हें प्रकाश नहीं, अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है, क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं। वरना, सिर्फ एक चीज जो हमेशा है, वह अंधेरा है। अंधकार शाश्वत है। अगर मैं कहूं – 'दिव्य अंधकार' तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। दूसरे स्तर पर, जब हम शिव कहते हैं, तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं, वह जो आदियोगी या पहले योगी हैं, और जो आदिगुरू, या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे योगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं, उसके जनक शिव ही हैं।

योग, इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने, और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग भीतरी बोध से आया है।

यह सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले, मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। हजारों साल पहले, हर उस तरीके की खोज की जा चुकी थी, जिससे मानव तंत्र को परम संभावना में रूपांतरित किया जा सकता है। मानवता के इतिहास में पहली बार किसी ने इस संभावना को खोला कि आप अपनी पूरी चेतना में अपनी वर्तमान अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित हो सकते हैं। आदियोगी ने बताया कि आपका जो वर्तमान ढांचा है, यही आपकी सीमा नहीं है। आप इस ढांचे को पार कर सकते हैं और जीवन के एक पूरी तरह से अलग पहलू की ओर बढ़ सकते हैं। शिव का त्रिशूल जीवन के तीन मूल पहलुओं को दर्शाता है। योग परंपरा में उसे रुद्र, हर और सदाशिव कहा जाता है। ये जीवन के तीन मूल आयाम हैं। शिव को हमेशा त्रयंबक कहा गया है, क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। अगर तीसरी आंख खुल जाती है, तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल जाता है जो कि भीतर की ओर देख सकता है। शिव का वाहन नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है, वह कुदरती तौर पर ध्यानमग्न हो सकता है।

वह जो नहीं है ...

सूत्र

शिव शब्द 'वह जो नहीं है' और आदियोगी, दोनों की ही ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव, जो एक योगी हैं और वह शून्यता, जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने यह अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वह खुद ही है। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है।

दूसरा पहलू

कनाडा में कार चोरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। वर्ष 2022 में कार चोरी पिछले साल के मुकाबले 24 फीसदी बढ़ी।

टोरंटो में किसी की कार सुरक्षित नहीं है

डेनिस विल्सन को जब भी अपनी नई एसयूवी से जाना होता है, तब कार निकालने में उन्हें अतिरिक्त पंद्रह मिनट लगते हैं। पहले वह कार की स्टीयरिंग व्हिल में लगा लॉक अलग करते हैं, फिर चारों टायरों में लगे ताले खोलकर कार निकालते हैं। उनकी कार में दो अलार्म सिस्टम लगे हैं, साथ ही, उनके पास व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस भी है। यही नहीं, टोरंटो स्थित अपने आवास पर उन्होंने गैरेज में दो फ्लडलाइट्स भी लगा रखी हैं। फिर भी कार की सुरक्षा के प्रति वह आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि टोरंटो के होशियार कार चोर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कार चुरा ही लेते हैं। विल्सन को आशंका है कि एक न एक दिन चोर उनकी यह कार भी उठा लेंगे, जैसे पहली कार चुरा ले गए थे।

ज्योसा एसाई

कार चोरी के बढ़ते मामलों से लोगों में गुस्सा है, तो विपक्षी पार्टी इसे सरकार की अक्षमता के रूप में देखती है। कारों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं।

कार चोरी की बढ़ती घटनाओं को राष्ट्रीय संकट की तरह देखा जा रहा है। अकेले 2022 में बीमा कंपनियों ने कार मालिकों को 89 करोड़ डॉलर के दावों के भुगतान किए।

कनाडा में कार चोरी के मामले अप्रत्याशित तेजी से बढ़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, वर्ष 2022 में कार चोरी की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 24 फीसदी वृद्धि हुई। उसमें भी टोरंटो में चोरी के मामले सर्वाधिक देखे गए हैं। वहां पिछले छह साल में कार चोरी की घटनाओं में 150 फीसदी वृद्धि हुई है, जिससे कार मालिकों में चिंता और गुस्सा है।

विपक्षी पार्टी कार चोरी के बढ़ते मामलों को सरकार की अक्षमता के रूप में देखती है, तो कारों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। कुछ धनाढ्य लोग अपनी कार गोपनीय जगहों में सुरक्षा गार्डों और कुत्तों की निगरानी में रखने लगे हैं। स्थिति इतनी विकट है कि पिछले महीने राजधानी ओटावा में आनन-फानन में कार चोरी की घटनाओं पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चिंतित प्रधानमंत्री जस्टिन त्रुदो को कहना पड़ा कि संगठित अपराधी गिरोह बेहद ताकतवर हो गए हैं और चुराई जाने वाली कारों का वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

वह बैठक दरअसल नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए बुलाई गई थी कि सरकार अपराधी गिरोहों पर नजर रख रही है, कार चोरी पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और सीमा सुरक्षा मजबूत की जा रही है। चोरों का दुस्साहस तो इतना है कि उन्होंने पूर्व और मौजूदा कानून मंत्रियों के सरकारी वाहनों तक को नहीं बख्शा।

कार चोरी की बढ़ती घटनाओं को कनाडा में राष्ट्रीय संकट की तरह देखा जा रहा है। इंश्योरेंस ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, कार चोरी के कारण अकेले 2022 में बीमा कंपनियों ने कार मालिकों को 89 करोड़ डॉलर के दावों के भुगतान किए।

©The New York Times 2024

आंकड़े

प्रति व्यक्ति वस्त्र

वर्ष 1961 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति मात्र 15 मीटर कपड़ा उपलब्ध था, जो अब बढ़कर तीन गुने से ज्यादा हो गया है।

(आंकड़े मीटर में) | स्रोत : Economic Survey

माता पार्वती को सप्तऋषियों ने समझाया कि शिव औघड़ हैं और उनसे विवाह करके तुम सुखी नहीं रहोगी, लेकिन वह अपने विचारों पर दृढ़ रहीं।

माता पार्वती की दृढ़ता

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध सती ने शिव से विवाह किया, जिसके कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया और भगवान शिव का अपमान भी किया। माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन शरीर त्यागते समय उन्होंने संकल्प किया था कि मैं हिमालय के घर जन्म लेकर फिर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी।

इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह 'पार्वती' कहलाईं। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि शिव औघड़ हैं, विचित्र वेशभूषा वाले हैं और तुम्हारे योग्य वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम सुखी नहीं रहोगी। लेकिन पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देख सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और मनोरथ सफल होने का आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। जिस दिन शिव-पार्वती का विवाह हुआ, उस तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। *(अमर उजाला आर्काइव से)*

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 5 अप्रैल, 1955

लखनऊ के नए रेडियो स्टेशन का उद्घाटन

लखनऊ रेडियो का नया स्टेशन
१३ अप्रेल को उद्घाटन
लखनऊ, ४ अप्रेल। लखनऊ के ५० किलोवाट के नये रेडियो स्टेशन का उद्घाटन १३ अप्रेल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द करेंगे। नया रेडियो स्टेशन लखनऊ नगर से ९ मील दूर

आगामी 13 अप्रैल को लखनऊ के 50 किलोवाट के नए रेडियो स्टेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद करेंगे। नया रेडियो स्टेशन लखनऊ नगर से 9 मील दूर लखनऊ-बाराबंकी रोड पर स्थित है।

समानता का मूल्य सबके लिए

लिंग तटस्थ कानून की मांग कुछ दशकों से उठ रही है, क्योंकि संविधान का मूल भाव बिना किसी लिंग भेद के समानता की प्रस्थापना करता है।

ऋतु सारस्वत | कानून

बीते दिनों इंदौर के परिवार न्यायालय ने एक पत्नी को भरण-पोषण के लिए हर महीने अपने पति को पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। अमूमन देश भर की अदालतों में पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश दृष्टिगोचर होते हैं। बेशक यह देश का ऐसा पहला मामला नहीं है, जहां वैवाहिक विवाद की स्थिति में एक पत्नी द्वारा पति को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए गए हों। लेकिन पिछले सात दशकों में ऐसे 'लिंग-तटस्थ' निर्णयों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। सितंबर, 1988 में 'ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी' के मामले में निर्णय देते हुए जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा था कि 'चूंकि पति की कोई स्वतंत्र आय नहीं है और प्रतिवादी पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 30 और 31 (मौजूदा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25) के अनुसार, पति को गुजारा भत्ता देने की स्थिति में है, अतः याचिकाकर्ता पति को सौ रुपये प्रति माह भरण-पोषण दिया जाए।' उल्लेखनीय है कि

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 'लिंग तटस्थ' है।

लिंग तटस्थ वह विचार है, जहां जैविक अंतर के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैधानिक स्तर पर विभेद परिलक्षित न हो। लिंग-तटस्थ व्यवस्था, बिना किसी व्यवधान के सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने का आश्वासन भी है।

अगर हम भारतीय वैधानिक व्यवस्था को इस संदर्भ में देखें, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 तथा 25 के प्रावधान लिंग तटस्थ हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मार्च, 2011 को 'रानी सेठी बनाम सुनील सेठी' मामले में कहा था कि 'हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का उद्देश्य ऐसे जीवनसाथी को सहायता प्रदान करना है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।' दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर पत्नी को, पति को बीस हजार रुपये देने का आदेश दिया था।

लिंग तटस्थ कानून की मांग विगत कुछ दशकों से उठ रही है और इसके पीछे स्पष्ट तर्क यह है कि जब संविधान का मूल भाव बिना किसी लिंग भेद के समानता की प्रस्थापना करना है, तो क्यों वैधानिक स्तर पर स्त्री विशेषाधिकार कानून हैं? इस तर्क को अयोग्य मानते हुए यह दलील दी जाती है कि चूंकि महिलाएं पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में प्रताड़ित और पीड़ित रही हैं, इसलिए उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कानून का एकपक्षीय होना न्यायसंगत है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं कि दुनिया भर में सहस्राब्दियों से महिलाएं हाशिये पर धकेल दी गई थीं और इसके विरोध में लैंगिक समानता का संघर्ष जन्मा। वैचारिक, सामाजिक तथा वैधानिक स्तर पर महिलाओं को सामान्य स्तर पर लाने की जद्दोजहद जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे लैंगिक समानता का वास्तविक अर्थ अपना अस्तित्व खोता चला गया।

'लैंगिक समानता' को मात्र महिलाओं की समानता समझना उसके अर्थ को खंडित करता है। लैंगिक समानता का वास्तविक और संपूर्ण अर्थ बिना किसी लिंग भेद के समानता स्थापित करना है। महिलाओं का समानता का संघर्ष एक संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित और अपरिहार्य भी है, परंतु यह कहना कि 'विश्व के सभी पुरुष क्रूर, असंवेदनशील तथा रूढ़िवादी हैं', दुर्भाग्यपूर्ण है।

बीते दशकों में शिक्षा, रोजगार तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और वह आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि वह अब भी स्वावलंबन का अपेक्षित स्तर अर्जित नहीं कर पाई हैं। परंतु यह मानना कि उनकी स्थिति दशकों पूर्व जैसी ही है, महिला सशक्तीकरण से संबंधित आंकड़ों से मेल नहीं खाता। दूसरी तरफ, 2017 में 'द मेलबॉक्स : ए स्टडी ऑन बीइंग ए यंग मैन इन द यूएस, यूके ऐंड मेक्सिको' अध्ययन पुरुष होने की पीड़ा को बखूबी बयान करता है। यह बताता है कि पुरुषों पर यह दबाव निरंतर बना रहता है कि वे अधिकाधिक धन अर्जित करें, जिससे उनका परिवार भौतिक संसाधनों को सहजता से प्राप्त कर सके। अगर किसी कारणवश वह अपेक्षानुरूप ऐसा नहीं कर पाते, तो उन्हें कमतर और नकारा माना जाता है। क्या यह आवश्यक नहीं कि लैंगिक समानता का वास्तविक अर्थ न केवल जाना जाए, बल्कि उसके प्रति सचेष्ट प्रयास किए जाएं?

edit@amarujala.com

दैनिक जागरण

आत्मचिंतन का अभाव प्रगति में अवरोध बनता है

नया जम्मू-कश्मीर

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री ने जिस नए जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया, उसकी एक झलक उनकी इस रैली में भी दिखाई दी। उसमें अच्छी-खासी संख्या में भीड़ जुटी और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक कठोर प्रबंध भी नहीं दिखे। इससे यही रेखांकित हुआ कि जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से घाटी का वातावरण बदल रहा है। कश्मीर का माहौल बदलने के संकेत पहले भी मिलते रहे हैं। बीते वर्ष कश्मीर में रिकार्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। वहां पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर देखने को मिल रही हैं और जन कल्याण एवं विकास योजनाओं के रफ्तार पकड़ने के साथ ही निवेश भी बढ़ रहा है। इसके अलावा सिनेमाघर खुलने के साथ उद्योग-धंधे फल-फूल रहे हैं। इसी तरह सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी सुगमता के साथ हो रही हैं। यह सब हो पा रहा है तो इसीलिए कि वहां आतंकी घटनाओं में कमी आई है और अलगाववादियों के हौसले पस्त हुए हैं। श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री ने 64 सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके कुछ दिनों पहले उन्होंने जम्मू में भी सैकड़ों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की अपनी रैली में एक ओर जहां अनुच्छेद 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किए जाने की याद दिलाई, वहीं दूसरी ओर इसका भी उल्लेख किया कि इस अनुच्छेद का कैसे चंद राजनीतिक परिवारों ने अपने हित में इस्तेमाल किया। यह एक सच्चाई भी है और इसीलिए इन परिवारों के नेताओं ने कश्मीर में स्थितियां सुधरने के प्रधानमंत्री के दावे का खंडन किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है, इसलिए विपक्षी दलों के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था में सुधार आने की बात पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी स्वीकार कर चुके हैं। वास्तव में इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कश्मीर की स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वहां सब कुछ सामान्य हो गया है और अब जम्मू-कश्मीर के हालात देश के अन्य राज्यों जैसे हो गए हैं। इस राज्य और खासकर कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने में समय लगेगा, इसका संकेत इससे भी मिला कि प्रधानमंत्री ने विकास और बदलाव की बातें तो कीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने की चर्चा नहीं की। यह तय है कि यह काम वहां विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही संभव हो सकेगा। इसके पहले वहां के हालात और सुधारने, पाकिस्तान का हस्तक्षेप बंद करने के साथ आतंकवाद पर पूरी तरह काबू पाना होगा। इसके साथ ही कश्मीरी हिंदुओं की वापसी भी सुनिश्चित करनी होगी। यह सब तभी हो सकेगा, जब कश्मीर की जनता यह संदेश और सही तरह ग्रहण करेगी कि उसका हित देश के साथ कदम मिलाकर चलने में है।

लापरवाही सही नहीं

पर्यटन राज्य के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश साहसिक खेलों में भी पहचान बना रहा है। यहां आने वाले पर्यटक साहसिक खेलों का भी आनंद ले रहे हैं। सरकार भी इन्हें बढ़ावा दे रही है। ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्केटिंग, स्कीइंग, नौकायन के अलावा कई जलक्रीड़ाएं आयोजित की जा रही हैं। कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बीच साहसिक खेलों के दौरान कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इनमें कहीं आयोजकों की लापरवाही सामने आती है तो कई बार पर्यटक सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। यह सही है कि जीवन में रोमांच होना चाहिए, लेकिन यह कतई सही नहीं है कि जानबूझकर जोखिम लिया जाए। होना तो यह चाहिए कि किसी भी साहसिक खेल में हिस्सा लेने से पहले देखा जाए कि जो व्यक्ति आयोजन करवा रहा है, क्या वह प्रशिक्षित है? क्या वह सरकार से मान्यता प्राप्त है? क्या वहां पर सुरक्षा के प्रबंध हैं? इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि उस समय मौसम की परिस्थितियां संबंधित खेल के अनुकूल हैं? यह इसलिए आवश्यक हैं, क्योंकि यहां पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बुधवार को पीज से कुल्लू के ढालपुर के तीन पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी, लेकिन तेज हवा के कारण एक पैराग्लाइडर पेड़ पर अटक गया। सुखद पक्ष यह रहा कि इसमें पायलट एवं पर्यटक सुरक्षित हैं। कई पर्यटक यहां आकर पहाड़ों पर अकेले ही ट्रैकिंग पर चले जाते हैं। ऐसा करना भी कतई सही नहीं है। साहसिक खेलों के दौरान हमेशा दुर्घटना की आशंका रहती है, इस कारण आयोजकों और खेलप्रेमियों को चाहिए कि हर तरह के नियमों का पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन को भी समय-समय पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करनी चाहिए।

साहसिक खेलों के आयोजकों एवं भाग लेने वालों को नियमों की अनदेखी से बचना होगा

राजवंश सरीखी राजनीति

गिरीश्वर मिश्र

भारतीय राजनीति में नए नेतृत्व का प्रजा के बीच से न उभरना और नेताओं द्वारा अपने परिवार को थोपने का रुझान चिंताजनक है

अवधेश राजपूत

आगामी चुनाव अमृतकाल के संकल्पों की जमीनी यात्रा की दृष्टि से भी महत्व का होगा। अगले 25 वर्षों में हम कहां पहुंचेंगे, यह प्रश्न भारतीय जनता के मन को मथ रहा है। विगत कुछ वर्षों में सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने के लिए उठाए गए कदमों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सुविधाएं बढ़ी हैं। कई मोर्चों पर कामयाबी मिली है। हालांकि यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि सब कुछ ठीक है। अभी भी बहुत कुछ सुधार करना शेष है। संप्रति राजनीतिक परिदृश्य पर जनता की कम और राजनीति के नए-पुराने किरदारों की भूमिका ही अधिक दिखती है। कुछ थोड़े से लोग ही लोकतंत्र के यज्ञ चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, जबकि जनता के लिए अच्छी सरकार उसकी आकांक्षाओं के पूरा होने के लिए जरूरी है। निश्चय ही विश्व के विशालतम जनतांत्रिक देश के लिए आम चुनाव परीक्षा की घड़ी जैसे हैं। चुनाव में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति में 'देश' की बड़ी अहमियत होती है। 'देश' शाब्दिक रूप से तो स्थान को बताता है, लेकिन वह व्यापक संदर्भों वाला एक विचार भी है और समाज का स्वप्न भी, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बसने वाली जनता को एक सशक्त भावनात्मक सूत्र में बांधता है।

देश में जल्द ही सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। देश चलाने के लिए अनेक छोटे-बड़े दल चुनावी दंगल में शामिल होने को आतुर हैं। उनकी बातों में देश के लिए और देश में उपेक्षित और हाशिए पर स्थित लोगों के लिए चिंताएं दिख रही हैं। इन वर्गों के लिए अनेकानेक प्रस्ताव भी पेश होते रहते हैं। भावी नीति-रीति को स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा घोषणापत्र जारी किया जाता है। अब 'संकल्प पत्र' भी जारी होते हैं। इन सबके बीच व्यापक मुद्दों पर बहस राजनीति से गायब हो रही है। स्वस्थ बहस और नीतिगत चर्चा का पटाक्षेप सा हो गया है। परस्पर दोषारोपण का अंतहीन सिलसिला चल निकला है। सत्ता की शक्ति का आकर्षण बेजोड़ होता है। उसके लिए नेताओं को किसी भी चीज से परहेज नहीं है। अतीत की ओर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के समय राजनीति का रिश्ता देश-सेवा और आत्मदान से जुड़ गया था। राजनीति से जुड़ने वाले व्यक्ति में निजी-हित एवं स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए समर्पण का भाव प्रमुख था। स्वराज के आकांक्षी यानी 'सुराजी' ऐसे ही होते थे। वे अपना खोकर सबका हो जाने की तैयारी से राजनीति में आते थे। स्वतंत्रता मिलने के साथ सरकार में भागीदारी ने राजनीति का चरित्र और उसका रूप-स्वरूप बदलना शुरू किया। देखते ही देखते नेताओं की वेश-भूषा एवं रहन-सहन आदि में बदलाव आया और जीवन की राह तेजी से आभिजात्य की ओर उन्मुख होती गई। विधायक या सांसद राजपुरुष होने की ओर बढ़ने लगे। मंत्री होना राजसी ठाट-बाट का पर्याय सा हो गया। नेताओं का भी दरबार लगने लगा और वे प्रजा की सेवा से दूर होते चले गए। जनसेवक होने की जगह वे खुद अपने लिए जनसेवा कराने लगे। अब इस तरह की व्यवस्था एक स्थायी रूप ले चुकी है। उसका शुद्ध रूप माननीयों के जनता दरबार में दिखता है, जहां लोग अपनी फरियाद के साथ हाजिरी लगाते हैं। राजनीति ने सेवा की जगह धन उगाही के व्यापार का रूप ले लिया और नेताओं की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी वाले हिसाब से बढ़ने लगी। देश भर के तमाम नेताओं की आर्थिक समृद्धि का ग्राफ जिस चमत्कारी ढंग से बढ़ने लगा, वह अपने में बहुत कुछ कहता है। प्रतीत होता है कि नेतृत्व करना या राजनीति का कर्म नेता के लिए धन-संपदा बटोरने का जरिया बन गया है।

आज अधिकांश नेताओं के पास आय से अधिक संपत्ति होना एक आम बात है। इसी के साथ एक पक्ष और प्रबल होने लगा कि नेता का परिवार और परिजन भी राजनीति में अवांछित दखल देने लगे। जन-सेवा और लोक संग्रह से कोसों दूर ये नए नवेले अगली पीढ़ी के नेता मुख्यतः कर्मठ जन-सेवा की बदौलत नहीं, बल्कि वंशधर होने के कारण उसमें शामिल होने लगे। राजनीति का जो आधार पहले जनता से जुड़ा था, वह दरकने लगा। अपने विश्वस्त की तलाश करते वरिष्ठ या 'सीनियर' नेताओं की आंखें घूम फिर कर अपने बेटी-बेटे, पत्नी, भाई, भतीजे और नाते-रिश्तेदारों पर टिकने लगीं। सच कहें तो राजनीति में भागीदारी उसके किरदारों को पुश्तैनी व्यापार जैसा लगने लगा। कई मामलों में जनता को भी नेता की थोपी हुई संतान में उसी नेता की छवि दिखने लगी। यह बात और है कि विरासत में मिला जनाधार टिकाऊ नहीं होता। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में खानदानी नेताओं की जमात बढ़ती जा रही है। राजनीतिक सरोकारों का इस तरह सिमटना देश और समाज के साथ-साथ नए नेता के लिए भी अहितकर होता है, लेकिन यह जानते-समझते हुए भी राजनीति में वंशवाद का बोलबाला बढ़ने पर है। राजनीतिक दल पारिवारिक दल में रूपांतरित हो जाता है और सत्ता का संपत्ति की भांति बंटवारा किया जाता है। असंतुष्ट होने पर परिवार टूटने के तर्ज पर पार्टी टूटती है। यह जनतंत्र की मूल प्रकृति और चरित्र के उलट बैठता है। जनतंत्र तो जन से चलता है। प्रजा में ही जनतंत्र का आत्मा बसता है। प्रजा और जन एकसमान होते हैं, परंतु नेताओं का प्रजा के बीच से न उभरना अत्यंत चिंताजनक है। शर्म और लिहाज को ताक पर रखकर राजनीतिक वंशों का आधिपत्य बनाए रखने की घटनाएं राजनीति और लोकतंत्र दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कही जा सकतीं।

वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उनसे लोकतंत्र की मुश्किलें बढ़ना तय है। खानदानी तौर पर राजवंश सरीखी राजनीति के प्रमुख दावेदारों की सूची बढ़ती जा रही है। स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति में इनके करतब सार्वजनिक रूप से उपस्थित हैं। भारत में विभिन्न दलों से आते ये परिवार और उनके परिजन सालों-साल राज-सत्ता पर आसीन होकर सीधे या परोक्ष नियंत्रण से राजनीति करते हुए हमारे देश की दशा बनाते-बिगाड़ते आ रहे हैं। लोकतंत्र के लिए वंशवाद खतरनाक है और राजनीतिक बिरादरी को इस पर विचार करना ही होगा।

(लेखक पूर्व शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

समान संहिता के केंद्र में आएं महिलाएं

नाइश हसन

समान नागरिक संहिता के निर्माण में लैंगिक समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए

महिलाओं के लिए न्यायसंगत नहीं मजहबी कानून। फाइल

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए दशकों पहले हमारे पुरखों ने यह महसूस कर लिया था कि भारत के पंथ आधारित निजी कानून महिलाओं को न्याय नहीं देते। लिहाजा उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। तभी से लैंगिक समानता पर आधारित कानून बनाने और निजी कानूनों में बदलाव की मांग उठने लगी। वर्ष 1971 में पूना में हुई महिला कांग्रेस के दौरान भी यह बात जोरदार तरीके से उठी और लैंगिक समानता तथा स्त्री गरिमा की बात को बल मिला। एक तरह से हम पिछले 150 वर्षों से समान नागरिक संहिता की दिशा में अग्रसर हैं। आज हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के प्रविधान मौजूद हैं, जो पहले नहीं थे। बस उत्तराधिकार, शादी, तलाक और बच्चों के संरक्षण के मामले में सभी समुदायों के अपने-अपने कानून हैं। यह कहना उचित ही होगा कि वे महिलाओं को वांछित अधिकार नहीं देते। आजादी के बाद से महिलाएं उन्हें लगातार चुनौती देती आ रही हैं। 1948 के बाद से कई ऐसे मौके आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता की वकालत की और अनुच्छेद-44 का हवाला दिया। 1985 में शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद-44 मृत होकर रह गया है। इसके बाद 1995 में सरला मुद्गल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद-44 के लिए संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार को अभी कितना समय लगेगा? 2003 में जान बलवत्तम केस में कोर्ट ने फिर कहा कि यह दुख की बात है कि संविधान के अनुच्छेद-44 को अभी तक लागू नहीं किया गया। 2017 में भी शायरा बानो केस के समय अदालत में यह मुद्दा उठा था।

इसमें दो राय नहीं कि समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील समाज की वकालत करती है, जिसे लागू होना ही चाहिए, लेकिन देखा यह गया कि इस पर सियासी दलों ने राजनीति करके महिलाओं को इस मुद्दे के केंद्र से गायब सा कर दिया। समान नागरिक संहिता की जरूरत को न्याय से जोड़ने के बजाय देश की एकता, अखंडता, एक देश-एक कानून, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक गोलबंदी की तरफ मोड़ दिया, जबकि कानून में सुधार की मांग का राष्ट्रभक्ति या एकता, अखंडता से कोई लेना-देना नहीं। फिर भी यह वोट की गोलबंदी से जुड़ा मुद्दा बन गया और महिलाओं के बजाय नेता, धर्मगुरु सामने आ गए। निजी कानूनों पर सवाल उठाना धार्मिक मामलों में दखल देना माना जाने लगा। धर्मगुरु आपे से बाहर होने लगे। इस मुद्दे का दो बड़ी सियासी पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने सांप्रदायीकरण भी किया। इस राजनीति ने महिलाओं का खासा नुकसान किया। उन्हें पता होना चाहिए कि महिलाएं किसी समुदाय की भेड़ें नहीं हैं, जिन्हें चरवाहा मजहबी डंडा लिए हांकता रहे। वे स्वतंत्र आवाज हैं और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पहल करके राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के एजेंडे में शामिल एक काम को पूरा तो कर लिया, लेकिन इस कानून के बारे में महिलाएं उनसे कुछ सवाल भी कर रही हैं। इस कानून के तहत लिव-इन रिश्ते में रहने वाले जोड़े को सरकार के सामने अपने दस्तावेज पेश करने होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हमारे समाज में प्रेम करने वाले जोड़ों को अक्सर मार डाला जाता है। समुदाय उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है। अगर इस साल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो इसकी गंभीरता का अहसास होता है। जैसे-नोएडा में वैलेंटाइन डे पर एक पिता ने बेटी की हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में एक भाई ने अपनी बहन को प्रेम करने की क्रूर सजा दी। गोंडा में तो बेटी के पिता ने बेटी एवं उसके प्रेमी, दोनों को मार डाला। ऐसे में अगर प्रेमी जोड़े अपने रिश्ते और उनके साथ रहने के बारे में हलफनामा देंगे तो उनके जीवन पर खतरे की तलवार मंडराने लगेगी और उनकी निजता प्रभावित होगी। ऐसा प्रविधान कानून में लाना यह साबित करता है कि कानून बनाते समय महिलाओं को नजरअंदाज किया गया। उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं सोचा गया। ऐसे कानून महिलाओं की गरिमा के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।

ऐसी संभावना है कि आगे और भी राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। लिहाजा उन्हें इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता का माडल उनके यहां की महिलाओं के नजरिये से मुफीद है या नहीं? जब सरकारें समान नागरिक संहिता के मसौदे पर बहस करें तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचार-विमर्श में सभी समुदाय की महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समानता का नजरिया उसके केंद्र में हो। इससे ही महिलाओं के लिए समानता की लड़ाई और प्रभावी हो सकेगी। साथ ही सरकारों और सामुदायिक नेताओं पर भी दबाव पड़ेगा कि वे महिला अधिकारों की बात को स्वीकार करें। एक आदर्श स्थिति तो वह होगी, जब हम पहले वैकल्पिक नागरिक संहिता लाएं, फिर निजी कानूनों में सुधार लाते-लाते अंततः एक अनिवार्य नागरिक संहिता को जन्म देने में सफल हो जाएं। समान नागरिक संहिता को एक बार में ही न लागू करके इसे चरणों में लागू किए जाने की जरूरत है। वैकल्पिक कानूनों की उपलब्धता स्वयं ही निजी कानूनों में सुधार की दिशा में काम करेगी। किसी भी धार्मिक संदर्भ को देखे बिना मानवीय आधार पर न्याय होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद की जाती है कि अन्य राज्य समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करते समय महिलाओं की आवाज को अनसुना नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम इतनी आशा तो कर ही सकते हैं।

(लेखिका महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शिव-पार्वती विवाह

धर्मग्रंथों के अनुसार देवाधिदेव महादेव के 14 बार डमरू बजाने से अंतरिक्ष में जो गूंज हुई उससे महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। महादेव की कृपा से ही महर्षि पाणिनि को यह सूत्र मिला इसलिए इसे उन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अक्षर महादेव के स्वरूप जैसे हैं। महादेव के सहस्र नामों में एक नाम अक्षर भी है। अक्षरों को संयोजित कर शब्द बने और उन शब्दों से अर्थ निकला, जिसके चलते भावों की अभिव्यक्ति शुरू हुई। इस प्रकार अक्षर शिव हैं और उनका संयोजन कर शब्द बनाने की प्रक्रिया पार्वती से दांपत्य सूत्र बंधन है। कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि 'मैं वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता-पिता पार्वती-शिव को प्रणाम करता हूं।' शिव-पार्वती के विवाह का आशय मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है। शब्द न होते तथा विचारों की अभिव्यक्ति न होती तो पूरी धरती पर पशुवत जीवन होता, क्योंकि पशु किसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं।

शिव तथा पार्वती के विवाह को भाव पक्ष और कर्म पक्ष के संयोग के अलावा चिंतन और क्रियान्वयन के रूप में भी देखा जा सकता है। मनुष्य का सकारात्मक चिंतन ही उसे देवत्व की ओर ले जाता है, नकारात्मक चिंतन दैत्य श्रेणी में ले जाता है। किसी सोची गई बात का क्रियान्वयन किस रूप में किया गया, यह महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य कर्म करके प्रकृति से शक्ति अर्जित करता है। स्मरण रहे कि कर्म पक्ष शिव और भाव पक्ष पार्वती है। स्त्री हो या पुरुष मानसिक स्तर पर दोनों कर्म तथा भाव के बंधन में रहते हैं। पुरुष में भी स्नेह, प्रेम, करुणा एवं दया का स्त्रियोचित भाव जब जागृत होता है तब वह नारी के गुणों वाला बन जाता है। जबकि स्त्री भी जब कर्म करती है तब उसमें पुरुष तत्व प्रधान हो जाता है। इसलिए शिव-पार्वती के विवाह का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व में संपूर्णता का समावेश है।

सलिल पांडेय

संबंधों के निर्वहन का साझा भाव

डा. मोनिका शर्मा

शिव-पार्वती की जोड़ी हर पति-पत्नी को यह समझाती है कि साथ और आपसी समझ ही इस रिश्ते की शक्ति है

पारिवारिक जुड़ाव को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाली भारतीय संस्कृति में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजनीय दांपत्य कई सार्थक पाठ पढ़ाता है। बिखरते रिश्तों के इस दौर में इस जुड़ाव को समझने का महत्व और बढ़ गया है। शिव-पार्वती की जोड़ी हर पति-पत्नी को यह समझाती है कि साथ और आपसी समझ ही इस रिश्ते की शक्ति है। दांपत्य जीवन में सहज स्वीकार का भाव ही वैवाहिक संबंध को मजबूती देता है। अपने साथी का संबल बनने की यह सीख आज आम दंपती के लिए भी जरूरी है।

महाशिवरात्रि का पर्व शिव-पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह स्मरण करवाता है कि उनके पूजनीय दांपत्य से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शिव-पार्वती का प्रेममयी दांपत्य सिखाता है कि अपने-आप को ही नहीं, अपनों को भी सहज रूप से अपनाया जाए। अपने परिवेश से जुड़ा जाए। उनका वैवाहिक जीवन अपने साथी को लेकर आत्मीय प्रेम और स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाने वाला है। आज रिश्तों में आ रही कि टूटन की बड़ी वजह इस स्वीकार्यता का न होना ही है। अब पारिवारिक व्यवस्था को सबसे ऊपर नहीं रखा जाता। जबकि सच तो यह है कि हमारे परिवारजन ही सुख-दुख के साथी होते हैं। जनमानस अपने परिवेश और प्रकृति से भी दूर होता जा रहा है। जबकि परिवार और समाज के साथ ही प्राकृतिक परिवेश से भी जुड़ाव आवश्यक है। प्रकृति के प्रति आभार और संरक्षण का सोच जरूरी है। शिव-गौरी का जीवन इस समभाव और कल्याणकारी सोच का भी पाठ पढ़ाता है, क्योंकि महादेव के परिवार का जीवन सरल और सहज है। सुख सुविधाओं से परे, पर स्नेह से सिंचित। तभी तो साधारण सा जीवन जीने वाले भगवान शिव और उनका परिवार वर्तमान में सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। प्रकृति से जुड़ाव और सहज जीवन आज आपाधापी में उलझे आमजन के लिए जीवन के हर मोर्चे पर एक सकारात्मक सीख लिए है।

वस्तुतः संतुलन साधते हुए जीवन जीना ही संतुष्टि का आधार तैयार करता है। दायित्व निर्वहन संग हर सुख-दुख को जीने का साहस देता है। भारत के पारिवारिक-सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दांपत्य जीवन की डोर भावनाओं और जिम्मेदारियों के धागों से ही बंधी होती है। आज मामूली बातों को लेकर टूट रहे पत्नी-पति के संबंधों को संवारने के लिए शिव-पार्वती के अनूठे रिश्ते को समझना चाहिए। ध्यातव्य है कि उनके आदर्श दांपत्य में स्वीकार्यता, सह-अस्तित्व और अपनेपन का भाव बहुत गहरा है। यही सोच सामान्यजन के लिए भी अनुकरणीय है। निःसंदेह पौराणिक चरित्रों के सार्थक संदेश और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारना आस्था के भाव का महत्व और बढ़ा देता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगे लगाम

पंकज चतुर्वेदी के 'गंभीर होती आवारा कुत्तों की समस्या' आलेख में बताई गई परेशानी आज देश के हर गांव, नगर, महानगर की है। वर्ष में दो बार प्रजनन करने वाले पशुओं की यह प्रजाति बेरोकटोक अपनी संख्या बढ़ा रही है। आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के झुंड ने काट कर घायल कर दिया। कुत्तों को लेकर सबसे गंभीर तथ्य तो यह है कि इनके काटने से होने वाली बीमारी लाइलाज है। दुनिया भर में उसका कोई इलाज नहीं है। मनुष्य के एक बार संक्रमित हो जाने के बाद उसे दर्दनाक मृत्यु ही मिलती है। इससे बचाव के टीके भी पर्याप्त मात्र में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं रहते। अक्सर ही उनकी किल्लत की खबरें आती हैं। यह सही है कि पशुओं में कुत्ते मनुष्य के अच्छे और वफादार साथी हैं, किंतु झुंड के झुंड घूमते आवारा कुत्ते नागरिकों के लिए समस्या ही बने हुए हैं। सरकारों को इस अति गंभीर विषय पर ध्यान देना चाहिए। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए हर जिले में कुत्तों के लिए एक बड़ा पुनर्वास केंद्र सरकारी स्तर पर बनाया जाना चाहिए, जिसमें नगरों में घूमते आवारा कुत्तों को पकड़ कर रखा जाए। नागरिकों को प्रेरित किया जाए कि वे इन कुत्तों के भरण-पोषण में सहयोग करें। कुत्तों की नसबंदी भी इनकी संख्या को सीमित करने का एक कारगर और बेहतर उपाय हो सकता है। जनसहयोग से सरकारें देश को इस समस्या से छुटकारा दिला सकती हैं।

राजीव वार्ष्णेय, पुरानी पैंठ, चंदौसी

मेलबाक्स

गरीबी दूर करने के उपाय

हाल में अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे देश में गरीबी कम हो रही है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में असामानता भी कम हुई है। यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी भारत को गरीबी पूरी तरह से दूर करने लिए बहुत करने की जरूरत है। मौसम चक्र के बिगड़ने के कारण दुनिया भर में इसका कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे महंगाई बढ़ रही है। अगर मुफ्त की योजनाओं या रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देकर गरीबी दूर करने के उपाय किए जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। यह देश के खजाने को खाली कर सकता है। विकास के काम थम सकते हैं। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। सरकार की सभी राष्ट्रीय योजनाओं का मकसद रोजगार बढ़ाना भी होना चाहिए। कुछ गरीब लोग अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिससे उनकी कमाई तो बढ़ती नहीं, उलटे गरीबी के दलदल में और धंस जाते हैं। फिर लोग गरीबी और अन्य समस्याओं के लिए सरकार को दोष देते हैं, अगर भारत को गरीबी मुक्त करना है तो देश में सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या और मुफ्तखोरी की योजनाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है।

raju09023693142@gmail.com

बड़बोले नेताओं का हो बहिष्कार

द्रमुक सांसद ए. राजा ने भगवान श्रीराम और भारत के बारे में जो बेतुका बयान दिया है वह बहुत ही निंदनीय है। यह उनकी संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाता है। राम हम सबके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कोई चुनावी रैली नहीं थी। उसमें हर राजनीतिक दल के नेताओं को जाना चाहिए था। बेहूदा बयान देने वाले राजनेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। जिस भी दल से वे संबंध रखते हैं उनको चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। जिससे उसके हाईकमान ऐसे बड़बोले नेताओं को अपने दल से बाहर का रास्ता दिखाएं। संविधान में सब धर्मों के लोगों को एक समान अधिकार मिले हैं तो पंथनिरपेक्षता के नाम पर पखंड करके धर्म-संप्रदाय की राजनीति करने की क्या जरूरत? कुछ राजनेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए पंथनिरपेक्ष को हिंदुपेक्षा बना दिया है। ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। मतदाताओं को राजनीतिक तौर पर जागरूक होना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

12.2 लाख करोड़ डालर है विश्व के 2,640 अरबपतियों की कुल संपत्ति। यदि विश्व के प्रत्येक अरबपति अपनी संपत्ति का 0.5 प्रतिशत भी दान करें, तो 61 अरब डालर की रकम जमा हो सकती है।

आजकल

वैश्विक शांति के लिए भारत का ठोस प्रयास

डा. अश्विनी महाजन
प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में हाल ही में डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में भारत ने चीन समर्थित प्रस्तावित विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते के रूप में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के प्रयास को मात दी है। कहा जा सकता है कि इस कदम से भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय प्राप्त की है, जिससे भारत स्वयं को एवं विश्व के कई अन्य देशों को भी चीन के आर्थिक चंगुल में आने से बचा सकता है। लिहाजा वैश्विक शांति की दिशा में भारत का प्रयास सार्थक होता दिख रहा है

अबूधाबी में हालिया आयोजित डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत को मिली कूटनीतिक विजय। डब्ल्यूटीओ

डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस बात पर भारी उत्सुकता दिखी कि क्या डब्ल्यूटीओ में एक और प्लूरिलेटरल समझौता (एक ऐसा समझौता जिसमें डब्ल्यूटीओ के कुछ ही देश शामिल होंगे) होगा, जिसका नाम है आइएफडीए (इनवेस्टमेंट फैसिलिटेशन फार डेवलपमेंट एग्रीमेंट) यानी विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता। इस प्रस्तावित समझौते को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था। डब्ल्यूटीओ एक बहुपक्षीय संगठन है। इसके अधिकांश समझौते बहुपक्षीय रहे हैं, जिन्हें सभी सदस्य देशों ने मान्य किया।

आइएफडीए : यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित एक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रविधान बनाना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय समझौता घरेलू नियमों के दायरे को सीमित करता है, आइएफडीए के मामले में यह स्थिति अधिक भयावह थी और निवेश सुविधा के नाम पर सदस्य देशों के संप्रभु अधिकारों की तिलांजलि दिए जाने का प्रविधान था।

भारत की चिंता : आम तौर पर समझौते तब बनते हैं जब देशों का एक समूह एक मान्य नियमावली पर सहमत होने के लिए इकट्ठा होता है, जिसका किसी मामले पर पालन किया जाएगा और यह एक दूसरे के लिए पारस्परिक लाभ के लिए होता है। हालांकि आइएफडीए की खासियत यह है कि इसके प्रस्ताव को एक देश (चीन) ने अपने लाभ के लिए आगे बढ़ाया और एक प्रमुख सैन्य व आर्थिक शक्ति चीन द्वारा दबाव डालकर अन्य सदस्यों से आंख मूंदकर हस्ताक्षर करवाए गए। चीन का एकमात्र उद्देश्य आइएफडीए सदस्य देशों को अपने-अपने देशों में निवेश की सुविधा के लिए मजबूर करके अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। पिछले एक दशक से चीन विकासशील देशों को स्वयं द्वारा बनाई जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्धार वित्तपोषण का लालच देकर ऋण जाल में धकेलने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। बेल्ट रोड की आड़ में चीन की ऋण जाल कूटनीति के कारण कई देश कर्ज में डूबे हुए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों को चीन अपनी इस कर्ज जाल कूटनीति से बर्बाद कर चुका है। प्रस्तावित समझौते से चीन को लूट और अधीनता के लिए नए चारागाह प्राप्त करने में आसानी होती।

आइएफडीए को कैसे रोका गया : चीन सहित कुछ वैश्विक शक्तियों के इशारे पर आइएफडीए को डब्ल्यूटीओ के दायरे में लाने के लिए डब्ल्यूटीओ सचिवालय की मदद से चीन का यह नापाक प्रयास वास्तव में पूरी तरह से अवैध था। अनुबंध 4 में बहुपक्षीय समझौते के रूप में आइएफडीए को जोड़ने की प्रक्रिया में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले, प्रस्तावित आइएफडीए व्यापार समझौते के रूप में योग्य नहीं था। आइएफडीए में व्यापार से संबंधित कोई ठोस प्रविधान शामिल नहीं है, और इसलिए इसे 'व्यापार समझौते' के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इन सब कानूनी कमजोरियों के आलोक में, आइएफडीए को डब्ल्यूटीओ में एकीकृत करने का बहुचर्चित प्रस्ताव अचानक ध्वस्त हो गया। चीन के नेतृत्व वाली इस कोशिश को आगे बढ़ाते समय नियम-आधारित डब्ल्यूटीओ स्वयं भी नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता। आइएफडीए में ऐसा कुछ भी नहीं था जो विकासशील देशों को विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सके।

इसके अलावा, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना एक संप्रभु या अन्य शब्दों में संप्रभु राष्ट्र के लोगों का विशेषाधिकार है, जिसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा कमजोर या कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। प्रस्तावित समझौते की विषय-वस्तु और संरचना के पीछे भयावह मंसूबे की मंशा प्रतीत होती हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि निवेश सुविधा उपायों के लिए वैश्विक मानक बनाने की आड़ में, वे संप्रभु देशों को अपने संबंधित क्षेत्रों में एफडीआइ को विनियमित करने और निगरानी करने के अधिकारों से वंचित करना चाहते थे। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है कि डोकलाम के बाद भारत ने उन सभी देशों से जिनकी भारत के साथ साझा सीमा है, पर एफडीआइ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। इस उपाय से भारत ऐसे देश से निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है जो भारत के साथ युद्ध में है। यदि हम इस समझौते की अनुमति देते हैं, तो देश अपने-अपने हितों की रक्षा करने की ऐसी किसी भी स्वतंत्रता से वंचित हो जाएंगे।

यह देखा जा रहा है कि आइएफडीए पर चीन ने दबाव डाला और बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) में भाग लेने वाले छोटे देशों की बांह मरोड़कर प्रस्ताव पर सहमति देने वाले अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। आरंभ में आइएफडीए का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका को भी बाद में भारत के साथ अपने संयुक्त बयान से पीछे हटना पड़ा। यह कोई रहस्य नहीं है कि बेल्ट रोड पहल के माध्यम से चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति के साथ अपनी कुटिल 'ऋण जाल' कूटनीति को प्रभावी बना रहा है। अपनी ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से चीन बीआरआइ में भाग लेने वाले देशों से प्रमुख रणनीतिक संपत्ति छीनने में सक्षम हो गया है और तेजी से वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए वैश्विक शांति के हित में आइएफडीए को किसी भी कीमत पर अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी, जो भारत प्रभावी ढंग से कर सकता था। इससे भारत विश्व में संप्रभुता और शांति की रक्षा करने में सफल हुआ है।

समुद्री केबल से मजबूत होगी भारतीय कूटनीति

नरेंद्र शर्मा

अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों द्वारा उत्पात जारी है। इस दौरान लाल सागर में चार केबल्स को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इससे विश्व के बड़े हिस्से में इंटरनेट सेवाएं दुष्प्रभावित हुई हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि केबल्स को नुकसान कैसे पहुंचा, लेकिन आरोप हूती विद्रोहियों पर लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समुद्री फ्लोर केबलिंग बड़ा भू-राजनीतिक खेल है, जिसमें भारत भी बड़ा खिलाड़ी है। फिर भी यह सवाल अपनी जगह है कि क्या हूती विद्रोहियों के पास समुद्र की गहराइयों में उतरकर केबल्स को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है?

वस्तुतः लाल सागर विश्व का अति व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। इस सागर की सतह पर 14 केबल्स बिछे हुए हैं, जिससे अफ्रीका व एशिया के बीच यह ग्लोबल इन्फो सुपर-हाइवे बन गया है। अंडर-सी केबल्स या सबमरीन केबल्स बुनियादी तौर पर समुद्र के तल पर बिछे कंडक्टर्स होते हैं। लाल सागर में जो 14 अंडर-सी केबल्स हैं, वे यूरोप व एशिया के बीच का 90 प्रतिशत नेट ट्रैफिक कैरी करते हैं। आजकल सभी केबल्स फाइबर आप्टिक होते हैं। इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि जब लाल सागर के चार केबल्स को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हांगकांग स्थित एचजीसी ग्लोबल कम्युनिकेशंस का कहना है कि चार केबल्स को नुकसान पहुंचने से एशिया व यूरोप के बीच 25 प्रतिशत डाटा ट्रैफिक दुष्प्रभावित हुआ है, जिसे अन्य केबल्स के जरिये री-रूट किया गया है, जिससे ट्रांसमिशन की स्पीड कम हो गई है।

बहरहाल, सवाल यह है कि वास्तव में क्या हुआ है और नुकसान किस हद तक का है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अंडर-सी केबल के इस भू-राजनीतिक खेल में भारत भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स हमेशा ही भू-राजनीति से संबंधित होते हैं। केबल्स डाटा कैरी करते हैं और डाटा का कामर्शियल व स्ट्रेटेजिक महत्व होता है। इसलिए युद्ध के समय में अपने दुश्मन का कम्युनिकेशन नेटवर्क काट देना बरीयता रहती है। पहले व दूसरे विश्व युद्धों के दौरान दुश्मन देशों ने एक-दूसरे के अंडर-सी केबल्स निरंतर काटे थे। जर्मनी की यू-बोट्स (सबमरीन) को तो विशेष रूप से दुश्मन के कम्युनिकेशन लिंक्स काटने का काम सौंपा गया था, बावजूद इसके कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ग्लोबल डाटा ट्रैफिक अपने शुरुआती दौर ही में था। आजकल तो ढंब पर बहुत अधिक है, क्योंकि अंडर-सी केबल्स के जरिये कैरी होने वाला डाटा अति विशाल है। किसी देश को ग्लोबल नेटवर्क से काट देना, उसे रणनीतिक रूप से अपंग बना देना होता है।

हाल के वर्षों में अनेक केबल्स को बिग टेक- गूगल, माइक्रोसाफ्ट व मेटा ने फंड किया है। भारत के भारती एयरटेल व रिलायंस जिओ ने भी सहयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय केबल्स में निवेश किया है। इन कंपनियों का व्यापार इंटरनेट ट्रैफिक पर ही आधारित है। इसलिए इन्हें वहां तो पैसा लगाना ही होगा जहां से मोटा मुनाफा आता है। भू-राजनीति में अमेरिका बनाम चीन को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? अगर डाटा नया तेल है, तो सुपरपावर्स के लिए उस पर अपने नियंत्रण का प्रयास स्वाभाविक है। जितने केबल्स आपके व आपके मित्र देशों के नियंत्रण में हैं, उतने डाटा फ्लो पर आपका प्रभाव है। चीन की तकनीकी कंपनियों जैसे हुआवेई पर अमेरिकी प्रतिबंध का एक कारण यह भी था। वस्तुतः वाशिंगटन को वे टेक कंपनियां पसंद नहीं हैं, जो अंडर-सी केबल्स को नियंत्रित करने के लिए बीजिंग से आदेश लेती हैं। सबमरीन केबल्स पुराने व्यापार मार्गों पर ही बिछे हुए हैं और इसलिए भारत पश्चिमी प्रशांत और फारस की खाड़ी के बीच अहम समुद्री चौराहा है। इसलिए नई दिल्ली को अंडर-सी केबल्स में अधिक निवेश करना चाहिए, ताकि भारत इस खेल में मुख्य खिलाड़ी बन सके और चीन व अमेरिका उस पर निर्भर होने को मजबूर रहें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
(ईआरसी)

खरी-खरी

युवा, कर्मठ और जुझारू के मायने

अलंकार रस्तोगी

जनाब अभी उम्र के सोलहवें पायदान पर पहुंचे हैं। देश की हिस्ट्री-जियोग्राफी के बारे में उतना ही पता है, जितने से इन सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स मिल सकते थे। लेकिन मोहल्ले की हर लड़की की हिस्ट्री-जियोग्राफी छोड़िये, फिजिक्स-केमिस्ट्री पर उनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल 18 साल की उम्र न होने के कारण देश में आयोजित हो रहे लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं दे पाने से ज्यादा मलाल उन्हें इस बात का है कि उन्हें 'ए' सर्टिफिकेट वाली फिल्में सिनेमा हाल में देखने के लिए अभी दो साल का और इंतजार करना पड़ेगा। वैसे इसकी खानापूर्ति जनाब अपने स्मार्टफोन से करके स्वयं को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं।

अपने गेटअप पर भी उनकी विशेष दृष्टि रहती है। फिजिक भले ही सिंगल पसली वाली हो, अलबत्ता शर्ट के चार बटन इस कदर खुले रहते हैं मानो जान अब्राहम ने इन्हीं से ट्रेनिंग ली हो। बिना लाइसेंस के जनाब धूम स्टाइल की बाइक पर इस गुमान में फर्राटा मारते हैं, क्योंकि उनकी अंटी में सर्वस्वीकार्य 'गांधी ब्रांड' लाइसेंस हमेशा पड़ा रहता है। सड़कों पर स्टंट करने को स्वराज्य की तरह वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं।

मां-बाप की दिखाई 'दिशा' से ज्यादा उन्होंने अभी तक 'दिशा पाटनी' की तरफ ध्यान दिया है। दुनिया के जितने भी ऐब हैं, उनमें से अधिकांश में सिद्धहस्त होने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह जनाब बियर की बोतलें गटक कर भविष्य में स्वयं को बार कल्चर में ढालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

सारे तथाकथित आधुनिक संस्कारों से लैस होने के बाद भी कोई लड़की उन्हें घास तक नहीं डालती है। लेकिन वह अपने इन सद्गुणों को बेकार नहीं करना चाहते हैं। अपने स्वर्णिम इतिहास के कारण वह स्वयं को युवा, कर्मठ और जुझारू कहलवाना पसंद करने लगे हैं। अपने सुखद भविष्य और स्वभावगत विशेषताओं के सदुपयोग के लिए उन्होंने अब एक राजनीतिक दल के सशक्त कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है।

पोस्ट

गाजियाबाद में गैस, शुगर और बीपी की एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा की नकली दवाएं पकड़ी गई है। कितने विश्वास के साथ लोग दवा खाते हैं कि ठीक हो जाएंगे। कैसे विश्वास किया जाए कि आप कौन सी दवाई खा रहे हैं?
आदित्य कुमार @Adityakripa

अगर भारत में फूड इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम ठीक से करें तो असंख्य लोगों की जान बचाई जा सकती है। नीलेश मिसरा @neeleshmisra

अंकिता भंडारी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। यह दुखद है कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी कोर्ट-कचहरी और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी को बर्दाश्त किया जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसे अपराधों पर त्वरित न्याय न मिलना निराशाजनक है।
आशीष नौटियाल @ashu_nauty

मुझे वह दौर भी याद है जब कश्मीर में भाजपा के कार्यक्रम में बमुश्किल पांच लोग जुटते और वे लोग भी चेहरा छुपाकर रखते थे। उसकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में तस्वीर एकदम बदली हुई दिखी। भयादोहन की वह मानसिकता अब हवा हो गई है। एक पूर्व सैन्य जनरल के शब्दों में कहूं तो कश्मीरी हमेशा विजयी खेमे की ओर रहना पसंद करते हैं।
राहुल पंडिता @rahulpandita

जागरण जनमत कल का परिणाम

शाहजहां शेख का बचाव करने से ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान होगा?

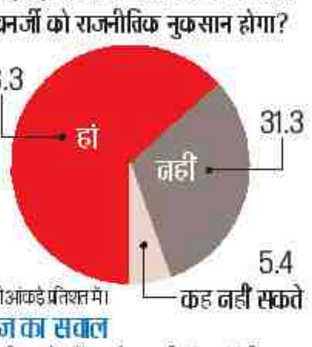

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड संबंधी सूचना साझा करने के लिए और समय मिलना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अमरीका में देखिए दो बूढ़ों की जंग,
वोट पड़ेंगे जब वहां खूब जमेगा रंग।
खूब जमेगा रंग जवानी कुछ तो सीखो,
भिड़े बाइडन-ट्रंप हौसला उनका देखो।
यदि होती बेमेल जंग तो लगता फीका,
अब जोड़ी यह देख मौज लेगा अमरीका।
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

सहानुभूति के सहारे सियासी सफर

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

भारतीय राजनीति में सहानुभूति की बड़ी महिमा है। इस पर सवार होकर लोग लोकसभा और विधानसभा तक आसानी से पहुंच जाते हैं। सरकारें भी इसके बूते बनती-बिगड़ती हैं। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भी सफलता के इस प्रचलित फार्मूले को आजमाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनके स्थान पर राजनीतिक मोर्चा संभाला है। हेमंत सोरेन राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सर्वेसर्वा हैं। उनकी अनुपस्थिति में पार्टी की बागडोर संभालने और चुनावों में दमदार मौजूदगी के लिए एक स्टार प्रचारक का होना आवश्यक था। ऐसे में कल्पना सोरेन इस रिक्तता को भरने के लिए आगे आई हैं। गिरिडीह में झामुमो की एक सार्वजनिक सभा से उनकी राजनीति की कठिन डगर पर एंट्री हुई तो भावुकता से भरा उनका भाषण, उनके आंसू, पति को लेकर उनके मन की बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी।

हालांकि कल्पना की राजनीति में सक्रियता की पृष्ठभूमि इस वर्ष के आरंभ से ही बनने लगी थी, जब ईडी का घेरा उनके पति हेमंत सोरेन के इर्द-गिर्द कस रहा था। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलेगा, इसका अनुमान नहीं था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि विपरीत परिस्थिति आने पर हेमंत सोरेन पत्नी की ताजपोशी करेंगे। ईडी की पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो चम्पाई सोरेन का नाम आगे किया गया। यह परिस्थिति राजकाज से दूर रहकर परिवार और बच्चों के बीच व्यस्त रहने वाली उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की संगठन में सक्रियता का आधार बनी। उनका लक्ष्य विधानसभा चुनाव है, जो इस वर्ष के अंतिम माह में निर्धारित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो

कल्पना सोरेन। फाइल

ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को पीछे धकेल दिया था। कांग्रेस और राजद के सहयोग से हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई। इस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती अब कल्पना सोरेन के कंधे पर होगी। इसमें सफलता या असफलता भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनके सियासी सफर में सहानुभूति का बड़ा योगदान होगा, जिसका अंदाजा भाजपा को भी है। कल्पना की राह इस मायने में भी आसान नहीं होगी, क्योंकि लोकपाल और सीबीआइ के घेरे में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सांसद रिश्वत कांड में ताजा फैसले से वे संकट में पड़ सकते हैं। उम्रजनित बीमारियों की वजह से शिबू सोरेन ज्यादा सक्रिय भी नहीं हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन पर अधिक दारोमदार होगा।

गिरिडीह में अपनी पहली सार्वजनिक सभा में उनके आंसू बोले। बार-बार वह भावुक हुईं। उस स्थान पर माथा टेकने पहुंचीं जहां से शिबू सोरेन ने महाजनी कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद किया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब सोरेन परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन तमाम झंझावात के बावजूद झारखंड की राजनीति में झामुमो कभी अप्रासंगिक नहीं हुआ। झामुमो में कभी बार विखंडन भी हुआ। अलग-अलग समय में कई कद्दावर नेताओं ने अपनी अलग राह चुनी। कुछ फिर से वापस भी आए। जो अलग हुए, उनमें ज्यादातर टिक नहीं पाए। झामुमो ने सियासी गठबंधन के लिए नरम रवैया भी अपनाया। ज्यादा समय कांग्रेस का साथ दिया तो मौका मिलने पर भाजपा के साथ भी मिलकर सरकार बनाई। हेमंत सोरेन इस मायने में सफल रहे कि उन्होंने मोर्चा का नेतृत्व करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखाया। एक समय ऐसा भी था जब उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जाते थे। बदली परिस्थिति में उन्होंने आलोचकों का मुंह जहां बंद किया, वहीं कद बढ़ाने में भी कामयाब रहे। झारखंड से बाहर भी गतिविधि बढ़ाई और राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त आदिवासी नेता की छवि बनाई।

पति की इसी उपलब्धि की छांव में आगे बढ़ने की रणनीति कल्पना सोरेन की होगी। इसके अलावा वह उन भावुक मुद्दों के इर्द-गिर्द अपना अभियान बढ़ाएंगी जो झामुमो के आधार वोटों को आकर्षित करता है। झामुमोनीत गठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को आधार बनाकर गढ़ी गई है तो इसके पीछे कारण यही था कि चुनाव में यह वोट में तब्दील हो सके। चुनावी सफलता पर ही आगे का दारोमदार होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में अभी सोरेन परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती। कल्पना सोरेन को पारिवारिक मोर्चे पर भी सबको एकजुट रखना होगा। सफलता हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। अनुशासन के दायरे में पली-बढ़ी सेना अधिकारी की पुत्री कल्पना सोरेन ने विपरीत परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया तो उनकी राजनीतिक डगर आसान हो सकती है।

मंथन

परोपकार से जीवन में सुधार

मार्क सुजमैन
सीईओ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

भारत समेत विश्व के अन्य तमाम क्षेत्रों में परोपकार के माध्यम से लोगों के जीवन की सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता में व्यापक रूप से सुधार किया जा सकता है

विश्व में ऐसे नवोन्मेषकों की कमी नहीं है जो कई बड़ी चुनौतियों पर अपनी नजरें गड़ाए हैं। लेकिन क्या कोई विचार भर लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? लोगों की समस्याओं के समाधान में परोपकार की काफी भूमिका होती है, इतनी कि कई बार लोगों को इसका अहसास भी नहीं होता। भारत के मामले में तो ऐसा काफी हद तक सच है। हाल के वर्षों में देश में परोपकारी गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। इंडिया फिलैंथ्रापी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, हाइ-नेटवर्थ व्यक्तियों तथा कारपोरेशंस से मिलने वाले परोपकारी योगदानों में पिछले पांच वर्षों के दौरान 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 13 अरब डालर के स्तर तक जा पहुंचा। देश में परोपकारी क्षेत्र बढ़त के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक, स्वास्थ्य और विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नवोन्मेषकों को सशक्त बनाकर तथा उनके विचारों को व्यापक रूप से प्रभावी बनाकर उल्लेखनीय अवसर उपलब्ध कराता है।

संक्रामक रोगों के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर जारी लड़ाई में गेट्स फाउंडेशन को अपनी भूमिका पर गर्व है। इससे यह साबित होता है कि सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर परोपकारी गतिविधियों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वैक्सीन संबंधी वैश्विक संगठन वैक्सीन अलायंस (गावी) ने एक अरब से अधिक बच्चों के टीकाकरण को साकार करने में मदद दी है। ग्लोबल फंड से एचआइवी, टीबी व मलेरिया ग्रस्त 5.9 करोड़ लोगों को बचाया जा सका है।

वस्तुतः परोपकारी गतिविधियां चीजों को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा हम अकेले करने में सक्षम नहीं होते। हमारे फाउंडेशन में हम अपने कार्य विभिन्न देशों, उनकी सरकारों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर करते हैं, ताकि उन लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकें जो उन्होंने निर्धारित किए होते हैं। दरअसल परोपकारिता में जोखिम उठाने की क्षमता होती है और यह उन तमाम कमियों या दूरियों को भर सकती है जिनकी अन्यथा अनदेखी हो सकती है या जिनके लिए पर्याप्त अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता, यह उस स्थिति में ही प्रभावी होता है जब यह सरकारों, निजी क्षेत्रों या स्थानीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रयास करता है।

आज परोपकारिता के परिदृश्य में 15 वर्ष पहले के उस दौर से काफी बदलाव आ चुका है, जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी। दुनियाभर में परोपकारी प्रयासों ने कई जटिल किस्म की चुनौतियों से निपटने की बेहतर दृष्टि और अनुभव प्रदान किए हैं। मुझे भरोसा है कि परोपकारी लोगों एवं संगठनों की अगली पीढ़ी प्रयासों में तेजी लाएगी। साथ ही यह भी उम्मीद है कि वे नए विचारों को भी सामने रखेंगे जिनसे परोपकारिता के स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी।

भारतीय परोपकारिता जगत के विकासक्रम को देखना वाकई प्रेरणास्पद है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे फाउंडेशन ने भारत में कई परोपकारी जनों एवं संगठनों के साथ मिलकर काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने समूचे भारत में दस लाख महिला उद्यमियों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान देने की पहल की थी। अगले तीन वर्षों में यह पहल राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशनों, गैर-लाभ प्राप्त संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को कृषि एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से कमाई के लिए मददगार साबित हो सकती है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया के 2,640 अरबपतियों की कुल संपत्ति 12.2 लाख करोड़ डालर है। परोपकारी जन/ संगठन मिलकर एक अरब डालर के फंड से ऐसे अधिक प्रभावशाली, कम खर्चीले कार्यक्रमों की शुरुआत कर सकते हैं जिनकी मदद से वर्ष 2030 तक और 20 लाख माताओं एवं शिशुओं का जीवन बचाया जा सकता है। इसी तरह से चार अरब डालर की निधि से लगभग 50 लाख छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तनों की मार से बचने के उपायों को लागू करने और 2030 तक कृषि गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में एक गीगाटन प्रति वर्ष तक कमी लाने में मदद दी जा सकती है। सात अरब डालर का फंड लगभग 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण में सहायक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 70 लाख लोगों को असमय मौत से बचाया जा सकता है।

नवोन्मेषी सुधार कार्यक्रमों से लाया जा सकता है बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में सुधार। प्रतीकात्मक

यदि विश्व का प्रत्येक अरबपति अपनी संपत्ति का 0.5 प्रतिशत भी दान करता है, तो 61 अरब डालर की रकम जमा हो सकती है। इससे उपरोक्त सभी लक्ष्यों को पूरा करने के बाद भी 49 अरब डालर की रकम बच जाएगी।

आज विश्व में कई तरह की जटिल समस्याएं सिर उठा चुकी हैं। अनेक नवोन्मेषक उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। दुनियाभर में वे ऐसे समाधान प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं जिनसे लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया जा सकता है। ऐसे कुछ समाधान जरूरतमंद लोगों तक पहुंच भी चुके हैं। बेशक, इस दिशा में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन यदि दृढ़ इच्छाशक्ति से यदि कार्य को अंजाम दिया जाए तो लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल नहीं।

****